Steel Quota released to M/s Sekhar Tubes Ltd. Ghaziabad

223. SHRI K. LAKKAPPA:
SHRI R. L. P. VERMA:

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) what are the products being manufactured by M/s Sekhar Tubes Limited, Ghaziabad;

(b) how much steel quota is being released by his Ministry to them every year;

(c) details for the quota released for the last three years and how much quantity was utilised by the Company for the manufacture of their products;

(d) whether his Ministry has received complaints that the steel quota is being sold by them in black market, and if so, details thereof and action proposed to be taken in the matter and

(e) if not, what checks his Ministry has over the company that the steel quota released by Government is utilised for *bona fide* purpose?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) M/s. Sekhar Tubes Ltd. are engaged in the manufacture of Tubes

(b) and (c). As there is no statutory control over iron and steel, no quota is released by this Ministry However, because of increased demand during the last year and availability being limited, a system of allocation of HR coils and skelp to the tube makers and others was introduced with effect from June 1978 so as to ensure equitable distribution. During June 1978 to June 1979 an allocation of 1850 tonnes of HR coils/skelp was made by Deptt. of Heavy Industry and from June 1978 to March 1979 about 1361 tonnes was supplied to the firm. Supplies made during the last three years were as under—

1976-77	—	Nil
1977-78	—	86 Tonnes
1978-79	—	1872 Tonnes (Provisional)

(d) An inspection of the unit was conducted by the Regional Iron and Steel Controller, Kanpur in February this year, as a result of which supply of iron and steel material to the party was suspended for a period of three months pending further inquiries in the matter However, the suspension order has been revoked as the unit was not found guilty of misutilisation of steel

(e) In order to check misutilisation of steel the operation of Clause 7 of the Iron and Steel (Control) Order has been revived As mentioned above; the unit was inspected and investigation conducted of the suspected misutilisation of steel. But actually no misutilisation was found to have taken place

कोहलगांव सुपर तापीय बिजलीघर के बारे में निर्णय

224. डा० रामजी सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) बिहार में ऊर्जा संकट के कारण कितने सरकारी और गैर-सरकारी नलकूप और लघु उद्योग एवं मध्यम स्तर के उद्योग बन्द हो गए हैं,

(ख) उन के परिणाम स्वरूप प्रति माह कुल कितना नुकसान हो रहा है,

(ग) क्या इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोहलगांव सुपर तापीय बिजलीघर के बारे में शीघ्र ही निर्णय करने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) यद्यपि ऊर्जा-संकट के कारण किसी लघु अथवा मध्यम उद्योग के बन्द हो जाने की सूचना नहीं मिली है किन्तु बिजली कम उपलब्ध होने के कारण उनके कार्यकरण पर आंशिक रूप से प्रभाव पड़ा है । इसी प्रकार, राजकीय तथा निजी नलकूपों के लिये भी बिजली की उपलब्धता काफी कम करनी पड़ी थी ।

(ख) इस प्रकार से बद हो जाने के कारण हुई किसी हानि की कोई सूचना नही मिली है । बिजली की कम सप्लाई होने के कारण हुई हानियो का मूल्याकन करना कठिन है क्योकि बिजली की कम सप्लाई के अलावा अन्य अनेक बातें ऐसी होती है जिन का प्रभाव औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन पर पडता है ।

(ग) और (घ) 1983–84 तक की अवधि के लिए बनाए गए विद्युत् कार्यक्रम में बिहार राज्य की कई निर्माणाधीन और हाल मे स्वीकृत की गई परियोजनाएं शामिल है । इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन से तथा उपलब्ध क्षमता के इष्टतम समुपयोजन से राज्य मे बिजली सप्लाई की स्थिति काफी सुधर जाएगी और सभावित माग इस से पर्याप्त रूप से पूरी हो जाएगी । विद्युत् आयोजन एक सतत प्रक्रिया है तथा समय समय पर विद्युत् कार्यक्रमो की समीक्षा की जाती है तथा इन्हे आगे बढाया जाता है । विशिष्ट समयावधि के लिए इष्टतम विद्युत् कार्यक्रम बनने मे सभी नए स्थलो का ध्यान रखना पडता है । कहलगाव मे एक वृहत् ताप विद्युत् केन्द्र स्थापित करने की तकनीकी तथा आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित करने के लिए और अन्वेषण करने आवश्यक है । इन अतिरिक्त अन्वेषणो के पूरा हो जाने और इस परियोजना की तकनीकी तथा आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित हो जाने के बाद ही एक उपयुक्त समयावधि के विद्युत् कार्यक्रम म कहलगाव परियोजना को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है ।

Abolition of Licence Fee for low cost Radios and Transistors

225 SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR

SHRI K A RAJAN:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state·

(a) whether it is a fact that Government are considering about the abolition of Licence fee of Rs. 7.50 per year on low cost radios and transistors and

(b) if so, what steps Government have taken in this direction so far?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) (a) and (b) The question of licence fee on radio receivers, including low-cost sets, is under consideration.

खानो के राष्ट्रीयकरण के बाद श्रमिकों की मंजूरी में वृद्धि

226. श्री राम नरेश कुशवाहा . क्या ऊर्जा मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) कोयला खानो के राष्ट्रीयकरण से पूर्व श्रमिको की मजूरी कितनी थी और अब कितनी है, और

(ख) इन मे किन तारीखों म वृद्धि की गई और कितनी वृद्धि हुई ?

ऊर्जा मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). कोयला उद्योग मे समय समय मजदूरो की न्यूनतम मजूरी (अन्य लाभो को छोड कर) का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

प्रभावी तारीख	न्यूनतम मजूदरी प्रतिमाह
	रु0
15–8–1967	163
31–12–1974	314
1–1–1975	424

मजदूरो के साथ अभी हाल में किए गए एक अतरिम समझौते के अनुसार एक मजदूर की न्यूनतम मजूरी 1–1–1979 से रु0 512 प्रति माह होगी । इस के अलावा 1-1-1979 के पहले भूमि के नीचे काम करने वाले मजदूरो को 10 प्रतिशत भूमिगत कार्य भत्ता मिलता था । दिनाक 1–1–1979 से यह भत्ता बढा कर मूल मजदूरी का 15 प्रतिशत कर दिया गया है ।

Implementation of Drugs Price Control Order, 1979

227. SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state

(a) whether it is a fact that the Drug industry has not been ready to implement the Drugs Price Control Order, 1979 so far despite repeated warnings by Government; and

(b) if so, the details and what action is proposed to be taken against them?